Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to recruit vacant professor post belong to Schedule Caste, Scheduled Tribes and OBC in Central Universities all aound the country.

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं ।

सभापति महोदय, हाल ही में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी द्वारा एक प्रश्न के जवाब में बताया गया था कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के पद रिक्त हैं । इन पदों की रिक्तता को भरने का काम केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का है । हम सभी जानते हैं कि इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा और शिक्षा के लिए सभी आयामों का इन्तेज़ाम करना, जिसमें नियुक्तियां भी शामिल हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय के आपसी समन्वय से होता है । नियुक्तियों की रिक्तता के बारे में माननीय मंत्री जी ने समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों के ऊपर डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया है ।

मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 40 प्रतिशत प्रोफेसरों के पद रिक्त हैं । इससे भी बड़ा दुर्भाग्य ओबीसी वर्ग के प्रोफेसरों का है । इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी वर्ग के प्रोफेसरों को मिलने वाले कोटे में लगभग 50 प्रतिशत से ऊपर ओबीसी प्रोफेसरों के पद रिक्त हैं । इन पदों को भरने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2019 में सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छः महीने के अंदर सभी आरक्षित पदों पर प्रोफेसरों की भर्ती का आदेश दिया था । एक अल्टीमेटम भी दिया था कि जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपने यहां आरक्षित प्रोफेसरों के पद को समय रहते नहीं भरते हैं, तो उनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिलने वाली ग्रांट रोक दी जाएगी । खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेश का न ही अनुपालन हुआ और न ही अनुपालन न करने वाले विश्वविद्यालयों की ग्रांट रोकी गई । **...(व्यवधान)**

माननीय सभापति: आप सिर्फ अपनी मांग रखिए ।

...(व्यवधान)

श्री गिरीश चन्द्र: सभापति महोदय, इससे समझा जा सकता है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच नूरा-कुश्ती किसी साजिश का अंश है । सरकार की मंशा पर झूठे दलित प्रेम और ओबीसी प्रेम पर प्रश्नचिन्ह लगना उचित है ।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि यदि वास्तव में भारत को विश्व गुरू बनाना है, तो पहले केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के प्रोफेसरों के रिक्त पदों को अविलंब भरा जाए । धन्यवाद ।